



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 117 राँची, मंगलवार, 24 माघ, 1938 (श०)
14 फरवरी, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

9 फरवरी, 2017

विषय:- शहरी स्थानीय निकायों में योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन में लोकसभा/विधान सभा के सम्बंधित माननीय सांसदों/विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

संख्या-8/विविध/116/2016/न०वि०आ०-1057-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय-17 में अंकित प्रावधान के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों को अपने राजस्व संसाधनों में वृद्धि करनी है ताकि प्राप्त राजस्व का उक्त शहरी स्थानीय निकाय के विकास हेतु समुचित उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नगरीय विकास से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के मद में सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों को सरकारी राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

2. सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के आंतरिक स्रोतों से उद्ग्रहित राशि तथा केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के मद में प्राप्त राशि का व्यय नगरीय विकास से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जाता है।

3. केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं तथा अन्य स्रोतों से विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध राशि से संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के बोर्ड द्वारा योजनाओं का चयन किया जाता है, किन्तु इस क्रम में लोकसभा/विधान सभा के सम्बंधित माननीय सांसदों/विधायकों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप इन जनप्रतिनिधिओं के द्वारा जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

4. उल्लेखनीय है की नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3873 दिनांक 28 अगस्त, 2014 की कंडिका-3 में निम्नांकित निर्णय संसूचित किये गए हैं :

4.1 राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को प्रक्षेत्रवार, यथा- सड़क निर्माण, नाली निर्माण, नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का निम्न रूपेण वितरण (Distribution) करते हुए व्यय किया जाएगा :

क्र०	प्रक्षेत्र	निकाय स्तर	वार्ड स्तर
1	नाली	40%	60%
2	सड़क	60%	40%
3	नागरिक सुविधा	80%	20%

4.2 कर्णांकित प्रक्षेत्रीय राशि का वार्डवार वितरण समस्त वार्डों की जनसंख्या एवं उनके क्षेत्रफल के आधार पर 50:50 के अनुपात में किया जाएगा।

4.3 किसी प्रक्षेत्र की वार्ड स्तरीय कर्णांकित राशि हेतु ऐसे वार्ड में योजना चयनित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित वार्ड समिति की अनुशंसा पर दो या दो से अधिक वार्डों के लिए उपयोगी योजनाओं में निकाय के बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत राशि व्यय की जा सकेगी।

4.4 किसी प्रक्षेत्र की वार्ड स्तर पर कर्णांकित राशि के व्यय नहीं किए जाने अथवा अवशेष रहने की स्थिति में निकाय स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं में इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

4.5 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा प्रक्षेत्रवार वार्षिक विकास कार्य योजना तैयार करते समय उक्त शहरी स्थानीय निकाय के लिए कर्णांकित प्रक्षेत्रीय बजटीय उपबंध की राशि की 1.25 गुणा लागत की योजनाएँ ली जा सकेगी, जिस क्रम में उपर्युक्त कंडिका 4.1 में वर्णित क्षेत्रवार कर्णांकण को ध्यान में रखा जाएगा।

4.6 इस क्रम में उक्त प्रक्षेत्र एवं क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान दायित्व (Current Liability) हेतु उक्त वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन हेतु आवश्यक राशि को घटाने के उपरांत अवशेष राशि के अंतर्गत ही नई योजनाएँ ली जा सकेगी।

5. निकाय स्तर हेतु कर्णांकित राशि के अन्तर्गत चयनित की जा रही योजनाओं के संबंध में यह आवश्यक है कि स्थानीय लोक सभा सांसद एवं स्थानीय विधायक की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिसके आलोक में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं :

- 5.1 शहरी स्थानीय निकायों को प्रक्षेत्रवार यथा, सड़क निर्माण, नाली निर्माण तथा नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध करायी गई राशि की 70% राशि के विरुद्ध संबंधित निकाय के बोर्ड के द्वारा निकाय स्तर की योजनाओं का चयन किया जाएगा, जिस क्रम में "अधिकतम जनसंख्या को अधिकतम लाभ" के सिद्धांत का पालन किया जाएगा ।
- 5.2 निकाय स्तर पर कर्णांकित अवशेष 30% राशि के विरुद्ध निकाय स्तरीय योजनाओं का चयन निम्नांकित प्रावधान के आलोक में किया जाएगा:

क्र०	निर्वाचित प्रतिनिधि	अनुशंसित योजनाओं का अधिकतम प्रतिशत
1.	महापौर/अध्यक्ष	10
2.	उपमहापौर/उपाध्यक्ष	5
3.	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी	5
4.	संबंधित निकाय के विधायक/लोक सभा के प्रतिनिधि	10

- 5.3 किसी निकाय क्षेत्र में एक से अधिक की संख्या में स्थानीय लोक सभा सांसद तथा स्थानीय विधायक के निर्वाचित रहने की स्थिति में, उनके लिए कर्णांकित राशि उनकी संख्या के अनुपात में विभाजित करते हुए यथा उपलब्ध राशि के अंतर्गत निकाय स्तरीय योजनाओं की अनुशंसा की जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
